संपादकीय जागरण

गुरुवार, 14 जून, 2018 : द्वि. ज्येष्ठ शुक्ल 1 वि. 2075

आंसू दर्द की मौन भाषा है

फिर वही धोखेबाजी

धोखा देने में माहिर पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की पीठ पर वार करने जैसा काम किया। संघर्ष विराम के प्रति नए सिरे से वचनबद्धता प्रकट करने के बाद भी वह अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आया। उसकी सेना ने जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों को जिस तरह अपना निशाना बनाया वह उसकी सोची-समझी चाल के अलावा और कुछ नहीं। हमारे सीमा प्रहरियों को पाकिस्तानी सेना के रवैये को लेकर और सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि चंद दिन पहले ही उसने संघर्ष विराम पर सहमति जताने के बाद उसका उल्लंघन किया था। उस समय भी हमारे जवानों को शहादत का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उसने फिर से संघर्ष विराम को लेकर हामी भरी, लेकिन किया वही जिसका अंदेशा था। मंगलवार की रात पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में सीमा सुरक्षा बल के चार जवानों की शहादत के बाद भारत यह बात गांठ बांध ले तो बेहतर कि पाकिस्तानी सेना की किसी बात पर भरोसा करने का मतलब है जानबूझकर धोखा खाना। पाकिस्तानी सेना की धोखेबाजी को इससे समझा जा सकता है कि पहले उसने सीमा सुरक्षा बल के दल पर गोलियां दागी और फिर अपने घायल साथियों की मदद के लिए गए जवानों को मोर्टार से निशाना बनाया। यह ठीक नहीं कि पहले भी सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक ने यह कहा था कि वादा करके मुकर जाना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और इस बार भी। जब वह पाकिस्तान के छल-कपट भरे व्यवहार से भली तरह परिचित थे तो फिर उन्होंने अपने जवानों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित सतर्कता क्यों नहीं बरती? सवाल यह भी है कि यदि पाकिस्तान फिर से संघर्ष विराम जारी रखने की बात करता है तो क्या भारत उसका स्वागत करने को तैयार होगा?

एक माह में सीमा पर आठ जवानों की शहादत सामान्य बात नहीं। पाकिस्तान की गोलाबारी में केवल सुरक्षा बलों को ही क्षति का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उनके साथ आम नागरिक भी पाकिस्तान के पागलपन का शिकार बन रहे हैं। इस साल अब तक 24 जवानों के साथ करीब 50 लोग पाकिस्तान की गोलाबारी का निशाना बन चुके हैं। यह एक बड़ी क्षति है। जनहानि के इस सिलसिले को स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह तो तथाकथित शांति काल में युद्ध काल सरीखा नुकसान है। भारत विरोध के उन्माद से ग्रस्त पाकिस्तानी सेना के कारण नुकसान का यह सिलसिला इसीलिए कायम है, क्योंकि एक तो उसे सही सबक नहीं सिखाया जा पा रहा है और दूसरे, भारत ने पाकिस्तान से लगती सीमा के निकट रह रहे आम लोगों और साथ ही सीमा रेखा की निगरानी करने वाले जवानों की सुरक्षा के लिए ठोस एवं स्थाई उपाय नहीं कर रखे हैं। कम से कम अब तो ऐसे उपाय किए ही जाने चाहिए। इसी के साथ पाकिस्तान को उसकी धोखेबाजी के लिए दंडित करने के नए तरीके आजमाने का भी समय आ गया है। निःसंदेह संघर्ष विराम के उल्लंघन पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाता है और इस दौरान उसे अच्छी-खासी क्षति भी उठानी पड़ती है, लेकिन शायद उतनी नहीं कि उसके होश ठिकाने आ जाएं।

आधुनिक बस अड्डे

प्रदेश सरकार एयरपोर्ट की तर्ज पर 22 बस टर्मिनलों को बनाने जा रही है। लखनऊ के आमलबाग टर्मिनल का लोकार्पण मंगलवार को किया जा चुका है। ये सभी पीपीपी मॉडल पर तैयार किए जा रहे हैं। लखनऊ के चारबाग और गोमतीनगर, इलाहाबाद के सिविल लाइंस, जीरो रोड, गाजियाबाद के कौशांबी एवं गाजियाबाद, कानपुर के झकरकटी, वाराणसी के कैंट, आगरा के फोर्ट, ईदगाह एवं ट्रांसपोर्टनगर, मेरठ के सोहराबगेट एवं भैसाली, बुलंदशहर के नवीन भूमि, अलीगढ़ के रसूलाबाद, गढ़मुक्तेश्वर के नवीन भूमि, बरेली के सेटेलाइट, मथुरा के पुराने बस स्टेशन का भी कायाकल्प होगा। गोरखपुर, फैजाबाद, रायबरेली के बस स्टेशनों का स्वरूप बदलेगा। इन टर्मिनलों के अलावा 22 अन्य बस अड्डों का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण किया जाएगा। सरकार ने इस बीच कई अन्य राज्यों से बसों के संचालन के लिए समझौता किया है।

बस यात्रियों को भी अब सुंदर और सुविधाजनक स्टेशन पर बैठ कर उसे गंदा करने से बाज आ जाना चाहिए

कई वर्षों से घाटे में रहने वाला उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अब मुनाफे में है। पिछले वित्तीय वर्ष में उसने 122 करोड़ का लाभ अर्जित किया। बहुत दिन बाद सड़क परिवहन को लेकर यह सुखद जानकारी मिल रही है। परिवहन निगम को सुधारने के कई प्रयास किए गए मगर इसकी सूरत कभी नहीं सुधरी। जो सरकार आई, उसने नई बसें खरीदीं। अपनी नीतियों के अनुरूप उनका नामकरण किया, बसों का रंग रोगन किया मगर कभी यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता में नहीं रखा। अब नए टर्मिनलों के बनने के बाद उसे बैठने का ठिकाना मिलेगा। बस यात्रियों को भी अब सुंदर और सुविधाजनक स्टेशन पर बैठ कर उसे गंदा करने से बाज आ जाना चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या ट्रंप और किम के बीच वार्ता तनाव दूर कर शांति एवं स्थायित्व की मुहिम को मजबूती देगी?

आज का सवाल

क्या अपील के बावजूद केजरीवाल के धरने में भीड़ का न जुटना उनकी घटती लोकप्रियता का संकेत है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

चुनौती पेश करते विपक्ष की मुश्किल

प्रदीप सिंह

विपक्षी एकता हो या न हो, लेकिन इतना तय लग रहा है कि 2019 का आम चुनाव मोदी के समर्थन और विरोध के मुद्दे पर लड़ा जाएगा

किसी भी सरकार के कार्यकाल का पांचवां साल सबसे अहम होता है। ज्यादातर यही साल यह तय करता है कि सरकार वापस आएगी या जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने जब अपने कार्यकाल का तीसरा साल पूरा किया था तो विपक्षी दल भी यह मानने लगे थे कि 2019 में मोदी सरकार का लौटना तय है और उन्हें 2024 की तैयारी करना चाहिए। नोटबंदी जैसे बड़े कदम के बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और भाजपा को अभूतपूर्व कामयाबी मिली। फिर जुलाई 2017 में मोदी सरकार ने अप्रत्यक्ष करों के मामले में आजादी के बाद सबसे बड़े टैक्स सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू किया। इसके बाद से कई ऐसी घटनाएं हुईं जिनसे लग रहा है कि 2019 की लड़ाई एकतरफा नहीं रहने वाली।

जीएसटी लागू होने के बाद तकनीकी और अन्य दूसरी जो दिक्कतें आईं उससे माहौल बिगड़ने लगा। चूंकि सरकार जीएसटी को लागू करने में आने वाली दिक्कतें लगातार दूर करती रही इसलिए धीरे-धीरे जीएसटी की गाड़ी पटरी पर आ गई। अब जीएसटी से मिलने वाला राजस्व लक्ष्य से ज्यादा हो गया है। जीएसटी लागू होने के बाद गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए। भाजपा को पिछले चुनाव की तुलना में 16 सीटें कम मिलीं। यह ऐसा चुनाव था जिसके लिए 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा मेहनत की। सूरत के व्यापारी जीएसटी से सबसे ज्यादा नाराज थे, लेकिन वहां की लगभग सभी विधानसभा सीटें भाजपा जीती। फिर सीटें कम क्यों हुईं? इसके दो बड़े कारण रहे। एक, पिछले 25-30 सालों में किसी राज्य में पाटीदार आंदोलन जैसा बड़ा जातीय आंदोलन नहीं हुआ था। दूसरे, सौराष्ट्र में कपास और मूंगफली की फसल का बाजार भाव गिरने से किसानों की परेशानी बढ़ी। यह सरकार के खिलाफ नाराजगी में तब्दील हो गई। विपक्ष को ऐसे ही किसी तिनके के सहारे की जरूरत थी। कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसकी वापसी हो रही है। यह भी कहा गया कि राहुल गांधी अब एक नए अवतार में आ गए हैं। गुजरात के बाद फरवरी-मार्च में त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव हुए। जिस त्रिपुरा में पिछली बार भाजपा की एक भी सीट नहीं थी वहां उसकी सरकार बन गई। भाजपा पहली बार वामदलों को हराकर किसी राज्य में सत्ता में आई। मेघालय में हार के बावजूद भाजपा कांग्रेस की काहिली के कारण सरकार बनाने में सफल रही-ठीक गोवा और मणिपुर की तरह से। नगालैंड में भी वह सहयोगियों की मदद से सत्ता में आ गई। इस तरह एक बार फिर पलड़ा भाजपा के पक्ष में चला गया, लेकिन पार्टी की इस खुशी को उपचुनावों का ग्रहण लग गया-पहले राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश एवं बिहार में। इससे विपक्ष के हौसले बुलंद हो गए।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के आंकड़े से नौ सीटें पीछे रह गई। यहां कांग्रेस ने वही किया जो भाजपा ने गोवा में किया था, लेकिन गोवा और कर्नाटक में एक बड़ा फर्क भी है। भाजपा ने गोवा में मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए सबसे कम सीटों वाली पार्टी को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी। इसके बाद हुए उपचुनावों में भी भाजपा ज्यादातर सीटें हार गई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और फूलपुर से शुरू हुई विपक्षी एकता ने कैराना के बाद और जोर पकड़ लिया। उपचुनावों में जीत को विपक्षी दल बदलती हवा का संकेत मान रहे हैं। पिछले चार साल में करीब 14 राज्यों में चुनाव जीतने (अकेले या सहयोगी दलों के साथ) की भाजपा की उपलब्धि के बरक्स विपक्ष उपचुनावों की जीत को अपनी बड़ी कामयाबी मान रहा है। 2019 में क्या होगा, इसका आकलन करने के लिए यह देखना जरूरी है कि 2014 में किस पार्टी की कितनी ताकत थी और आज क्या है? 2014 में मोदी राष्ट्रीय राजनीति के लिए नए थे। सवाल पूछा जाता था कि प्रदेश चलाने वाला देश कैसे चला पाएगा? भाजपा लस्त-पस्त हालत में थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वह तीसरे नंबर की पार्टी थी। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में उसके पास केवल नौ सीटें थीं। अब उपचुनाव हारने के बाद भी उसके विरोधियों के पास दस सीटों से ज्यादा नहीं। यहां लोकसभा की कुल 80 सीट हैं। भाजपा विधानसभा में 48 से 324 पर पहुंची थी। बिहार में उसके सहयोगी नीतीश कुमार साथ छोड़ गए थे, अब साथ हैं।

अवधेश राजपूत

बीते चार सालों में भाजपा ने महाराष्ट्र हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, असम, मणिपुर आदि में सरकार बनाई। यहां वह पिछले 15 सालों (कुछ में तो 70 सालों) में कभी सत्ता में नहीं रही। इसके अलावा वह उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, नगालैंड और नीतीश कुमार की वापसी के बाद बिहार में सत्ता में है। कर्नाटक में वह सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 2014 की तुलना में आज भाजपा पहले से ज्यादा मजबूत है। ओडिशा, बंगाल और केरल में उसका जनाधार बढ़ा है। 2014 की तुलना में एनडीए मजबूत नहीं तो कमजोर भी नहीं हुआ है। चंद्रबाबू नायडू निकले तो नीतीश कुमार की वापसी हुई। इसके बावजूद कुछ कमजोरियां भी आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अब 2014 की तरह सत्ता विरोधी रुख यानी एंटी इन्कबेंसी का फायदा नहीं है, बल्कि अब उन्हें उसका सामना करना होगा। इसके बावजूद अभी तक उपचुनावों को छोड़कर कहीं एंटी इन्कबेंसी नहीं दिखी है।

आजकल राजग में असंतोष के जो स्वर सुनाई दे रहे हैं वे बगावत के कम और सीटों की सौदेबाजी के ज्यादा हैं। इसके मुकाबले यदि विपक्षी खेमे पर नजर डालें तो वह पहले की तुलना में कमजोर ही हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भाजपा विरोधी दोनों पार्टियां-सपा और बसपा विधानसभा में क्रमशः 47 और 19 सीटों पर सिमट गईं। राहुल और सोनिया गांधी का नेतृत्व इन चार सालों में पंजाब के अलावा पार्टी को कहीं जिता नहीं पाया है। सिर्फ एक राज्य, पंजाब में कांग्रेस चार साल पहले की तुलना में मजबूत हुई है। वामदलों की हालत यह है कि जिस पश्चिम बंगाल में उन्होंने 34 साल राज किया वहां भाजपा उन्हें पछाड़कर दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है। बिहार में लालू यादव के जेल जाने के बाद तेजस्वी को साबित करना है कि जनाधार के मामले में वह पिता के उत्तराधिकारी हैं। विपक्षी खेमे में केवल एक नेता है जिसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है और वह हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। विपक्षी एकता हो न हो, लेकिन इतना तय लग रहा है कि 2019 का चुनाव मोदी के समर्थन और विरोध के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मोदी सरकार ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से मतदाता उसे दूसरा मौका देने को तैयार न हों। सरकार की तमाम उपलब्धियों के बावजूद ऐसे लोग जरूर हैं जो उसके काम से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिखता कि उनका असंतोष मोदी विरोध में बदल जाएगा। पिछले चार साल में तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी विरोधी ब्रांड मोदी को धूमिल करने में नाकाम रहे हैं। भाजपा के पास यही तुरुप का इक्का है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

फुटबॉल के रोमांच के लिए तैयार दुनिया

मनोज जोशी

यह फुटबॉल की पहुंच और लोकप्रियता ही है कि जहां संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 193 हैं वहीं फीफा के 214

जिस खेल आयोजन के विजेता को ढाई अरब रुपये और ग्रुप दौर से ही बाहर होने वाली टीम को करीब 54 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिलती हो उसकी भव्यता का अंदाजा स्वतः ही लगाया जा सकता है। जी हां बात 21 वें विश्वकप फुटबॉल की हो रही है, जिसका आयोजन रूस के 11 शहरों के 12 स्टेडियमों में हो रहा है। विश्वकप फुटबॉल आयोजन से 33 खरब रुपये की कमाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 31 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 64 मैच खेले जाएंगे। इस दौरान पूरी दुनिया फुटबॉल के रोमांच से सराबोर होगी। यह भी तय है कि भारतीय खेल प्रशंसकों का एक बड़ा वर्ग क्रिकेट से फुटबॉल की ओर शिफ्ट हो जाएगा। एक-एक किक करोड़ों रुपये की साबित हो सकती है। इस आयोजन की सबसे महंगी टिकट की कीमत लगभग 70 हजार रुपये की होगी, जबकि पिछले आयोजनों में यह कीमत और भी अधिक हुआ करती थी। विजेता को मिलने वाली ट्रॉफी तकरीबन 68 करोड़ रुपये की होगी, जो 18 कैरेट सोने की बनी होगी। माना जा रहा है कि दुनिया की करीब आधी आबादी इस खेल महाकुंभ को देखेगी।

इस टूर्नामेंट की महत्ता का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि चार बार की चैंपियन इटली, तीन बार की फाइनलिस्ट नीदरलैंड, कोपा अमेरिका कप की चैंपियन चिली और हाल में फ्रांस जैसी दिग्गज टीम से बराबर पर खेलने वाली अमेरिकी टीम क्वॉलीफाई ही नहीं कर पाई है। वहीं पेरू को 36 साल बाद, मिस्र और मोरक्को को 20 साल, ट्यूनीशिया को 16 साल बाद और पनामा को पहली बार विश्व कप में प्रवेश मिला है। टूर्नामेंट में भाग ले रही 32 टीमों को पिछले आयोजनों की तरह आठ वर्गों में बांटा गया है। हालिया फॉर्म को देखते हुए ब्राजील, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस की टीमें सबसे मजबूत मानी जा रही हैं। इनके बाद अर्जेंटीना, बेल्जियम, पुर्तगाल और इंग्लैंड का नंबर आता है। इन आठ टीमों में से छह यूरोप की हैं और दो लैटिन अमेरिका से। 1930 से चले आ रहे फुटबॉल विश्वकप में अभी तक यूरोप और लैटिन अमेरिकी देशों का दबदबा रहा है। यूरोप की टीमों ने 11 बार और लैटिन अमेरिका की टीमों ने नौ बार खिताब जीता है। दिलचस्प यह है कि 84 साल में केवल आठ देशों को ही चैंपियन बनने का अवसर मिला है। इनमें तीन टीमें लैटिन अमेरिका से (ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे) और पांच टीमें यूरोप (जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड) से हैं।

हाल के समय में यूरोपीय टीमें फुटबॉल की दुनिया में बढ़त पर हैं। दुनिया के किसी भी कोने में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर यूरोपीय क्लबों की नजर रहती है। यही वजह है कि मैसी और रोनाल्डिन्हो की पहचान बार्सिलोना क्लब से, एगुवेरो की मैनचेस्टर सिटी से और मार्सेलो की रियाल मैड्रिड से बनी है। रूस में विश्वकप फुटबॉल का यह पहला आयोजन होगा। उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पूर्व सोवियत संघ के रूप में 1966 के विश्वकप में था जब उसने सेमीफाइनल तक अपनी चुनौती रखी थी। रूस एक बड़ा देश है। उसके 11 शहरों के बीच काफी दूरी है। इसके चलते सभी टीमें ग्रुप दौर में ही करीब दो लाख किमी की दूरी तय करेंगी। एक तरह से वे रूस की संस्कृति के साथ उसके भूगोल से भी परिचित होंगी।

दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों की नजर तीसरा विश्वकप खेल रहे मैसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर खास तौर पर होगी, जिनके बीच फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनने को लेकर प्रतिस्पर्द्धा रहती है। इसी तरह उरुग्वे के लुइस सुआरेज, चोट से उबरे ब्राजीली स्टार नेमार, मिस्र के मोहम्मद सालाह, स्पेनिश गोलकीपर डेविड डे गिया और जर्मन गोलकीपर मैनुअल नोयर के बीच भी श्रेष्ठता की होड़ देखने को मिल सकती है। पिछले विश्वकप में सबसे अधिक छह गोल करने वाले कोलंबियाई मिडफील्डर जेम्स रॉड्रिग्स भी चर्चा में रहेंगे। हालांकि वह पिछले 39 क्लब मैचों में आठ गोल ही कर पाए हैं। इसी तरह जर्मन फॉरवर्ड थॉमस मूलर पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। वह विश्व कप के 13 मैचों में अब तक 10 गोल कर चुके हैं। फुटबॉल की पहुंच और लोकप्रियता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि आज संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश 193 हैं और फीफा के 214। फुटबॉल की लोकप्रियता के कारण इस खेल को एक संस्कृति के तौर भी जाना जाता है। एक संपूर्ण खेल के रूप में यह सेहत के लिहाज से उत्तम खेल है। कई देश इसलिए फुटबॉल को विशेष महत्व देते हैं ताकि किशोरों एवं युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देने में आसानी हो।

फुटबॉल विश्वकप में एशिया से सऊदी अरब, ईरान, कोरिया गणराज्य, जापान की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसी जोन में आता है। यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर भारत इस विश्व कप से दूर क्यों है? विश्व कप के हर आयोजन में यह सवाल उठता है और भारतीय फुटबॉल टीम को कोसने के लिए कुछ तर्क तलाश कर लिए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। भारतीय फुटबॉल सही दिशा में है। वह पिछले विश्व कप के दौरान अपनी रैंकिंग को 171 से 97 पर ले आया है। यानी बीते चार वर्षों में उसने 74 पायदान की ऊंची छलांग लगाई है। एशिया में भारत की रैंकिंग 14 है। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने भारतीय फुटबॉल के लिए टॉप टेन में आने का लक्ष्य रखा है। पिछले दिनों भारत ने मुंबई में आयोजित इंटर कांटिनेंटल कप अपने नाम किया। भारतीय टीम ने 2019 में होने वाले एएफसी एशियन कप के लिए भी क्वॉलीफाई किया है। बीते साल भारतीय फुटबॉल टीम विश्व कप चैंपियन जर्मनी और एक अन्य टीम बेल्जियम की तरह दुनिया की इकलौती ऐसी टीम थी जो साल भर अपराजित रही। भारत ने 2017 में 12 में से 11 मैचों में जीत दर्ज की और उसका एक मैच ड्रॉ रहा। स्टार खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक 64 गोल करने के मैसी के रिकॉर्ड की बराबरी की है। उनके अलावा आइएसएल के पहले सीजन के स्टार सेंटर बैक संदेश झिंगन और बेंगलुरु एफसी में सुनील छेत्री के शागिर्द उदांता सिंह के खेल को भी खूब सराहा गया है। हाल के समय में फुटबॉल के मामले में देश के घरेलू ढांचे में भी काफी सुधार हुआ है। अब सात से आठ महीने तक भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में व्यस्त रहते हैं। आइएसएल या आइ लीग के अलावा हीरो सुपर कप में खिलाड़ियों को लगातार मौके मिलते हैं। जाहिर है कि भारतीय फुटबॉल इस समय सही ट्रैक पर है। जरूरत बस और रफ्तार पकड़ने की है।

(लेखक खेल-विशेषज्ञ एवं कमेंटेटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सार्थक चिंतन

हम आप जीवन के पथिक हैं। हम आप एक व्यवस्था का पालन करते हैं। हमारे आपके पूर्वजों ने हमें आपको बहुत कुछ दिया है। प्रेम का प्रतीक, मर्यादा का प्रतीक, ईश्वर का प्रतीक, मन का प्रतीक आदि सब प्रतीक के रूप में हैं। कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हैं तो कहीं लीला प्रधान श्रीकृष्ण हैं। इसके पहले भी बहुत से लोग हुए, जो अपनी-अपनी लीला करके चले गए और आज भी बहुत से लोग हैं जो अपनी-अपनी लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन आपको वह इसलिए दिखाई नहीं देते, क्योंकि आपने उन आंखों को बंद कर रखा है। आप अपने अंदर छिपी उस पुण्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। आप भ्रमित होकर यहां-वहां पूछने जाते हैं। इसीलिए आप कमजोर हो जाते हैं।

यदि आपको अपनी साधना पर विश्वास है, आस्था है तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा। प्रकृति सोचती है कि यदि सभी मनुष्य बुद्धिमान हो जाएं तो यह चंचलता नहीं रहेगी। बुद्धि तो चंचल है, लेकिन मन नहीं। मन बुद्धि से चंचल नहीं है। बुद्धि मन से ज्यादा शक्तिशाली है। आपके मन में जब कभी भी विचलन आता है तो उसका कारण आपका मन नहीं, बल्कि उसका कारण तो आपकी बुद्धि है। दरअसल बुद्धि हमेशा चिंतन से सक्रिय होती है। वह आपके अधीन नहीं है। वह आपके भीतर है, लेकिन बाहर किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करती। आज के चिंतकों ने बहुत सी चीजों को खोज रखा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पुराने चिंतकों ने कभी इसे खोजने का प्रयास नहीं किया।

इसे जानने की कोशिश न तो आधुनिक संतों ने की और न ही आधुनिक वैज्ञानिकों ने। फलस्वरूप दोनों में दूरियां हो गईं। एक सत्य को खोज रहा है तो एक धार्मिक रहस्य को। एक आत्मीयता की खोज विज्ञान के माध्यम से करना चाहता है तो दूसरा अपने शरीर, मन, बुद्धि से परे जाकर ध्यान की गहराई पर उतरना चाहता है। दोनों में कोई साम्य नहीं है। हम जो यज्ञ करते हैं, वह भी एक विधि ही तो है। हममें से जो भी कोई इस यज्ञ में भाग लेता है, वह स्वयं को भगवद्-सत्ता से जोड़ने की कोशिश करता है। हमारा संकल्प आप लोगों को समर्थ व बलवान बनाने के लिए और आपके अंदर छिपी हुई क्षमता को जगाने के लिए है। हम आपकी जरूरत नहीं हैं, आप हमारी जरूरत हैं। इसलिए हम सबको अपने महत्व को समझना पड़ेगा कि हम कौन हैं।

महायोगी पायलट बाबा

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

प्रशासनिक क्षेत्र में राष्ट्रहितैषी प्रयोग

प्रो. निरंजन कुमार ने अपने आलेख 'प्रशासन को प्रभावी बनाने वाला फैसला' के माध्यम से उस विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की है, जो मोदी सरकार द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में किए जाने वाले एक राष्ट्रहितैषी प्रयोग से पैदा हुआ है। हैरत है कि केवल राजनीतिक विरोध के चलते विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार के एक ऐसे कदम की आलोचना की जा रही है, जो देश के प्रशासन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। माना कि प्रशासनिक कार्यों के संपादन के लिए देश में आइएएस स्तर के अधिकारियों को चयनित करने की एक पारदर्शी सुदृढ़ व्यवस्था है। लेकिन यदि देश के प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरुस्त और विशेषज्ञता से परिपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिभाशाली विशेषज्ञ पेशेवरों को प्रयोग के तौर पर संयुक्त सचिव स्तर पर अस्थाई रूप से नियुक्त करने का केंद्र सरकार ने फैसला किया है तो इस पर विपक्ष द्वारा अनावश्यक की हायतौबा क्यों की जा रही है? इस संबंध में विपक्षी दलों का यह आरोप कि इस सीधी भर्ती के बहाने मोदी सरकार आरएसएस के लोगों को प्रशासनिक क्षेत्र में लाना चाहती है, उतना ही बेबुनियाद और अतार्किक है, जितना यह कहना कि इस व्यवस्था से आइएएस कैडर के हित प्रभावित होंगे। क्योंकि यह सीधी भर्ती न तो पीएमओ कार्यालय द्वारा की जा रही है और न ही चयनित होने वाले पेशेवर विशेषज्ञों को स्थाई रूप से संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया जा रहा है। इस व्यवस्था में एक पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत पूरे देश से ऐसे मेधावी स्नातक पेशेवरों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं जो 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। अनुभवी विशेषज्ञों की एक टीम इनका साक्षात्कार करके चयन करेगी। यह टीम संघ लोक सेवा आयोग की भी हो सकती है। भला इस पारदर्शी प्रक्रिया से आरएसएस के लोग कैसे भर्ती हो पाएंगे? और किस तरह से आइएएस कैडर का हित प्रभावित होगा? बावजूद इसके एक राष्ट्रहितैषी प्रयोग का दूषित राजनीति के तहत अनुचित विरोध जारी है, जो राष्ट्रहितों के सर्वथा विपरीत है।

pandeyvp1960@gmail.com

राजनीति के भेंट चढ़े सरकारी आवास

उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी आवासों को खाली करने के तहत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने बंगले को 2 जून को खाली कर दिया। हालांकि जितनी चर्चा अखिलेश यादव के बंगले की हो रही है, शायद ही किसी और बंगले की हो। इस बंगले को खाली करने से पहले जिस तरीके से इसके अंदर तोड़-फोड़ की गई है, वह निंदनीय है जो एक मुख्यमंत्री स्तर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। इस तरह की हरकत अगर कोई सामान्य आदमी करे तो बात समझ में आती है, लेकिन मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहकर भी इस तरह का कृत्य कहीं से भी शोभनीय नहीं है। अगर राजनीतिक स्तर पर कोई आपसी मनमुटाव है तो उसे विचारों तक ही सीमित रखना चाहिए न कि निर्जीव चीजों के साथ ऐसी हरकत करनी चाहिए।

नीरज कुमार पाठक, आइसीएआइ, नोएडा

भय्यूजी महाराज ऐसे तो नहीं थे

विशाल हृदयी, गहरी सूझबूझ, आध्यत्मिकता से परिपूर्ण, औरों के मन से दुखदर्द मिटाने वाले व भटकों को सही राह दिखाने वाले गुरुजी के मन में ऐसा क्या ना सुलझने वाला गहरा वज्रपात समा गया कि वे समझदार होकर भी अपनी जीवन लीला समाप्त करने की नादानी कर बैठे। अतः भय्यूजी महाराज तो हमारे बीच नहीं रहे, किंतु उन्होंने अपने जीवन से औरों का जीवन सुधारने का जो संदेश सबको दिया है, उनको सहृदय अमल में लाएं यही उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजली होगी।

mahesh_nenava@yahoo.com

अब पाक की बारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के बीच जिस सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई, वह सचमुच दुनिया को शांति के रास्ते पर अग्रसर करने वाली सिद्ध हो सकती है। पहली ही मुलाकात में कोई नेता यह ऐलान नहीं कर सकता कि वह अपने सारे परमाणु हथियार नष्ट कर देगा, लेकिन कम से कम उस दिशा में प्रयास करने का वादा तो कर ही सकता है। किम जोंग उन ने कुछ यही किया है। कुछ दिनों पहले तक एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां करने वाले इन नेताओं को साथ बैठा देखना सचमुच अद्भुत था। समूची दुनियाभर से प्रतिबंध झेल रहा उत्तर कोरिया आज कंगाली व भुखमरी के कगार पर है और ऐसे में उसके शासक को एहसास हो गया कि परमाणु हथियारों के दम पर दूसरे मुल्कों को चिढ़ाकर वह अपने लोगों को भोजन व अच्छा जीवन नहीं दे सकता। वह जान गया कि आज भले ही जनता उसके डर के साये में खामोश है, लेकिन एक न एक दिन अवश्य चिंगारी भड़केगी और फिर कहीं उसकी स्थिति लीबियाई तानाशाह गद्दाफी जैसी न हो जाए। इस ऐतिहासिक मुलाकात के बाद अब उम्मीद है कि कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। इस सुखद अनुभव के बीच अब पूरी दुनिया को चाहिए कि दक्षिण एशिया में शांति कायम करने के लिए पाकिस्तान को भी उत्तर कोरिया की भांति अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करने पर बाध्य करे। उत्तर कोरिया के संदर्भ में चीन व अमेरिका ने साथ मिलकर इस देश को शांति की राह पर लाया और अब पाक के मामले में भी कुछ ऐसा ही करने की आवश्यकता है। आतंकवाद को अपने शासन का अभिन्न अंग बना चुके पाक को दी जाने वाली तमाम आर्थिक मदद तब तक के लिए बंद कर देनी चाहिए, जब तक कि वह अपनी रीति-नीति में बदलाव को तैयार नहीं हो जाता।

स्नेह प्रभा झा

ट्वीट-ट्वीट

मैं शतरंज खिलाड़ी सौम्या स्वामीनाथन से सहमत हूं कि वह खुद तय करें कि उन्हें हिजाब पहनना है कि नहीं। महिलाओं के लिए पहनावा तय करना उनका असम्मान करना है भले ही यह ईरान में हो या हरियाणा की खाप पंचायत द्वारा।

बरखा दत्त@BDUTT

सीमा पर शांति को लेकर पाकिस्तान के साथ बनी नई समझ को दो हफ्ते हो गए हैं, लेकिन इस बीच दो भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद चार अन्य जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मोदी का मुख्य योगदान यही है कि भारत अभी भी वही सॉफ्ट पावर बना हुआ है जिसमें सुधार नहीं हो सकता।

ब्रह्मा चेलानी@Chellaney

आखिरकार केजरीवाल और उनके शागिर्दों ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि उन्हें प्रशासन में नहीं, बल्कि धरना प्रदर्शन में ही महारत हासिल है। दिल्ली की जनता ने उन्हें अप्रत्याशित जनादेश दिया था और वह तबसे ही त्रस्त हो गई है।

तवलीन सिंह@tavleen_singh

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की माफी सभी को स्वीकार्य है और वह उसके बाद भी स्टार बनी हुई हैं, लेकिन अतुल कोचर की माफी हमारे लिबरल और सेक्युलरिस्टों को स्वीकार नहीं है। अब वे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। उनके लिए यही उदारवाद है।

अंशुल सक्सेना@AskAnshul

जनपथ

मत आना भाई मेरे करने को अहसान,
भले तुम्हारे बिन चली जाय हमारी जान।
जाय हमारी जान अगर तुम वहां पधारे,
तो कैसे अहसान चुकाएंगे हम प्यारे!
बनी सियासत आज ओढ़ना और बिछाना,
तो ऐसे संबंध निभाने तुम मत आना।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी* दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 330